



24 नोट्स	6 खबरें जोड़ी गईं	GS2 • 15 पेपर मिश्रण	GS3 • 9
-------------	----------------------	-------------------------	---------

विषय सूची

सभी नोट्स, पेपर के अनुसार

GS2	राज्यव्यवस्था • शासन • सामाजिक न्याय • अंतर्राष्ट्रीय संबंध	15 नोट्स
	राज्यव्यवस्था एवं संविधान	4
	शासन	1
	सामाजिक न्याय	2
	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	8
GS3	अर्थव्यवस्था • विज्ञान-तकनीक • पर्यावरण • सुरक्षा	9 नोट्स
	अर्थव्यवस्था	7
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1
	आंतरिक सुरक्षा	1

हर नोट में

चर्चा में क्यों → याद रखने योग्य तथ्य → कीवर्ड के साथ मेन्स प्रश्न। एक ही खबर की रिपोर्टें जोड़ दी गई हैं।

समय कम है?

5 पेज के सार में सबसे ज़रूरी खबरें और अभ्यास प्रश्न हैं।

राज्यवस्था एवं संविधान

4

EXECUTIVE (PRESIDENT, PM, GOVERNOR, CM)

P

8 सितंबर • The Hindu • satyadheesh.in/news/119181

विनई कुमार सक्सेना को मिली J&K की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

चर्चा में क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति के दौरान जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल विनई कुमार सक्सेना को नियुक्त किया है।

पद	विनाय कुमार सक्सेना: लद्दाख के उप-राज्यपाल।
पद	मनोज सिन्हा: जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल (Lieutenant-Governor)।
पद	न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
तथ्य	नियुक्ति 8 सितंबर, 2026 को की गई थी।

मेन्स प्रश्न जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक ढांचे और उपराज्यपाल की भूमिका की चर्चा कीजिए।

ELECTIONS, ECI & ELECTORAL REFORMS

P

8 सितंबर • The Hindu • satyadheesh.in/news/118963

मद्रास हाई कोर्ट ने एस. जयकुमार की जीत को सही ठहराया, ECI के प्लान पर असर

चर्चा में क्यों मद्रास उच्च न्यायालय ने थप्पु वेंकटाचलम द्वारा पेरुन्दुरई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एस. जयकुमार की विजय को चुनौती देने के लिए दायर चुनावी याचिका को खारिज कर दिया है।

स्थान	पेरुन्दुरई तमिलनाडु की एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है।
तथ्य	S. Jayakumar ने 9,693 मतों के अंतर से पेरुंडुराई विधानसभा सीट जीती।
संस्था	भारत निर्वाचन आयोग (ECI) उपचुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार निकाय है।

मेन्स प्रश्न भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायिक निरीक्षण के महत्व और उपचुनावों के समयबद्ध संचालन पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए।

STATUTORY, REGULATORY & QUASI-JUDICIAL BODIES

P

M

8 सितंबर • NDTV • satyadheesh.in/news/118932

दिल्ली में 50 साल से पुरानी DDA बिल्डिंग्स का होगा सेफ्टी ऑडिट

चर्चा में क्यों सत्य निकेतन में हुई एक घातक इमारत गिरने की घटना के पश्चात, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 50 वर्ष से अधिक पुरानी दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की इमारतों के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट और पुनर्विकास कोष की योजना की घोषणा की।

संस्था	दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA): दिल्ली में नियोजन और विकास के लिए उत्तरदायी निकाय।
तथ्य	50 वर्ष से अधिक पुरानी इमारतों के लिए सुरक्षा ऑडिट का प्रस्ताव।
तथ्य	ऑडिट की आवृत्ति प्रत्येक तीन से दस वर्ष में प्रस्तावित है।

मेन्स प्रश्न दिल्ली जैसे तेजी से विस्तारित होते महानगरीय क्षेत्रों में पुराने शहरी बुनियादी ढांचे की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS

P

8 सितंबर • The Hindu • satyadheesh.in/news/118888

राजस्थान हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने संजय कुमार अग्रवाल

चर्चा में क्यों Supreme Court Collegium की सिफारिश के आधार पर, न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई।

पद	न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल: राजस्थान उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश।
स्थान	लोक भवन: राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह का स्थल।
तथ्य	यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की Collegium की सिफारिश पर आधारित थी।

मेन्स प्रश्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 की मौत, अब ऑडिट पॉलिसी बनेगी

चर्चा में क्यों सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मृत्यु होने के पश्चात, दिल्ली सरकार पुरानी इमारतों के लिए संरचनात्मक ऑडिट और सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य करने हेतु एक नीति का प्रारूप तैयार कर रही है।

स्थान	सत्य निकेतन: दिल्ली में पांच मंजिला इमारत ढहने का स्थान।
संस्था	MCD: Municipal Corporation of Delhi, भवन निरीक्षण और आधिकारिक निलंबन के लिए जिम्मेदार निकाय।
तथ्य	सत्य निकेतन भवन ढहने से सात लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई।

मेन्स प्रश्न वृद्ध होते शहरी बुनियादी ढांचे की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली संस्थागत चुनौतियों और आपदा निवारण में नगर निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

सामाजिक न्याय

ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले फूड्स पर लगेगा वार्निंग लेबल

चर्चा में क्यों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार हेतु उच्च शर्करा, नमक या वसा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए एक चेतावनी लेबल प्रणाली का प्रस्ताव दिया है।

संस्था	FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India।
तथ्य	88% उत्तरदाता बड़े और स्पष्ट चेतावनियों को प्राथमिकता देते हैं।

मेन्स प्रश्न अनिवार्य खाद्य लेबलिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के माध्यम पर गैर-संचारी रोगों (NCDs) के समाधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

दिल्ली में हॉस्टल की समस्या दूर करने के लिए NHRC का बड़ा आदेश

चर्चा में क्यों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को 15 अक्टूबर, 2026 तक एक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

संस्था	NHRC: National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)।
संस्था	UGC: University Grants Commission।
तथ्य	व्यापक योजना के लिए NHRC की समय-सीमा: 15 अक्टूबर, 2026।
तथ्य	PG भवन के ढहने से सात लोगों की मृत्यु।

मेन्स प्रश्न शहरी शैक्षिक केंद्रों में सुरक्षित और किफायती छात्र आवास सुनिश्चित करने में आने वाली संस्थागत चुनौतियों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विनियामक निकायों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

INDIA'S BILATERAL RELATIONS

P

3 रिपोर्टें जोड़ी गईं

8 सितंबर • NDTV • satyadheesh.in/news/119166

भारत और बांग्लादेश के बीच फिर शुरू होंगी ट्रेनें, हाई कमिश्नर ने की मीटिंग

चर्चा में क्यों भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाओं को पुनः आरंभ करने के विषय पर चर्चा करने हेतु बांग्लादेश के सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री शेख रबीउल आलम से भेंट की।

स्थान	कोलकाता और न्यू जलपाईगुड़ी प्रस्तावित सीमा पार ट्रेनों के लिए प्राथमिक भारतीय प्रस्थान बिंदु हैं।
स्थान	पुनर्जीवित ट्रेन सेवाओं के लिए ढाका और खुलना प्रमुख बांग्लादेशी गंतव्य हैं।
संस्था	इंटर-गवर्नमेंटल रेलवे मीटिंग (Inter-Governmental Railway Meeting) एक वार्षिक द्विपक्षीय मंच है जिसका उपयोग सीमा पार रेल कनेक्टिविटी के लिए तिथियां निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

मेन्स प्रश्न भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और व्यापार को कैसे उत्थरित किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

INTERNATIONAL INSTITUTIONS & AGENCIES (UN, WTO, IMF...)

P

M

3 रिपोर्टें जोड़ी गईं

8 सितंबर • The Hindu • satyadheesh.in/news/119145

UNGA चर्चा में UN के मैप पर भारत ने उठाए सवाल

चर्चा में क्यों भारत समर्थित 'कोरेक्ट द मैप' (Correct the Map) प्रस्ताव पर UNGA की चर्चा के दौरान, विदेश मंत्रालय ने UN के मानचित्रों में विसंगतियों की आलोचना की और अरुणाचल प्रदेश एवं अक्साई चिन के पारंपरिक चिह्नों को शामिल न करने पर ध्यान आकर्षित किया।

तथ्य	'Correct the Map' प्रस्ताव 4 सितंबर, 2026 को पारित किया गया था।
स्थान	UN मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अनिर्दिष्ट दावा रेखाओं के बीच अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया था।
तथ्य	UN मानचित्र में जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) को एक बिंदु वाली रेखा (dotted line) के रूप में दिखाया गया था।
संस्था	'Correct the Map' प्रस्ताव का उद्देश्य महाद्वीपों, विशेष रूप से अफ्रीका और भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के सापेक्ष आकार के गलत चित्रण को संबोधित करना है।

मेन्स प्रश्न अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में मानचित्र संबंधी सटीकता के महत्व और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर विवादित सीमा चित्रण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

INDIA'S BILATERAL RELATIONS

P

M

2 रिपोर्टें जोड़ी गईं

8 सितंबर • Al Jazeera • satyadheesh.in/news/119059

12 सितंबर को ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन नई दिल्ली पहुंचेंगे

चर्चा में क्यों ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ एक नए युद्धविराम की संभावना के लिए मध्यस्थता करने हेतु BRICS शिखर सम्मेलन के अवसर पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं।

तथ्य	शीर्ष सम्मेलन की अवधि के दौरान Brent crude oil की कीमत लगभग \$97 प्रति बैरल के आसपास थी।
स्थान	हॉर्मुज जलडमरूम (Strait of Hormuz) वह प्राथमिक समुद्री गलियारा है जहाँ ईरान शिपिंग को लक्षित कर रहा है।
संस्था	BRICS सदस्यों और उनके भागीदारों ने वर्तमान संघर्ष में अब तक के प्रत्येक युद्धविराम की मध्यस्थता की है।
तथ्य	इस्लामाबाद मेमोरेंडम में पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम \$300 बिलियन की योजना शामिल थी।

मेन्स प्रश्न क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में ब्रिक्स (BRICS) ब्लॉक की भूमिका और मध्य पूर्व में वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

INDIA'S BILATERAL RELATIONS

P

M

8 सितंबर • Al Jazeera • satyadheesh.in/news/119053

इजराइली सेटलमेंट्स पर यूके के कड़े एक्शन से अमेरिका और इजराइल नाराज

चर्चा में क्यों यूके के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली बस्तियों पर प्रतिबंध शासन और आयात प्रतिबंध की घोषणा की है, जिससे अमेरिका और इजरायल की ओर से आलोचना हो रही है।

पद	एड मिलिबैंड: UK विदेश मंत्री।
तथ्य	UK-Israel वार्षिक व्यापार: £6 बिलियन।
स्थान	वेस्ट बैंक: UK प्रतिबंधों द्वारा लक्षित अधिग्रहित क्षेत्र।

मेन्स प्रश्न प्रमुख शक्तियों द्वारा लगाए गए एकपक्षीय प्रतिबंधों के क्षेत्रीय भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों और बस्ती विस्तार को रोकने में इन उपायों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।

ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर राफेल ग्रीसी की चेतावनी

चर्चा में क्यों | IAEA प्रमुख राफेल ग्रीसी ने चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा सहयोग की कमी और परमाणु स्थलों तक पहुंच का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, जबकि पश्चिमी शक्तियाँ (फ्रांस, जर्मनी, UK, US) इसे UN Security Council के पास भेजने पर जोर दे रही हैं।

संस्था	IAEA: International Atomic Energy Agency।
तथ्य	ईरान के परमाणु संवर्धन (uranium enrichment) ने महत्वपूर्ण सुविधाओं में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की है।
स्थान	ईरान परमाणु मुद्दे के लिए UN Security Council (UNSC) के पास रेफरल की मांग की गई।
पद	राफेल ग्रीसी: IAEA के प्रमुख।

मेन्स प्रश्न परमाणु प्रसार को रोकने में अंतराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) जैसे अंतराष्ट्रीय निगरानी निकायों की भूमिका और संप्रभु राष्ट्रों द्वारा असहयोग के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

गाजा में मलबे को हटाने पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, युद्ध अपराध के सबूत मिट सकते हैं

चर्चा में क्यों | संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनियुक्त (Special Rapporteur) ने चेतावनी दी है कि गाजा में मलबे को हटाने की इजराइल की कार्रवाई, 2024 में अंतराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, युद्ध अपराधों के साक्ष्यों को नष्ट कर सकती है।

संस्था	International Court of Justice (ICJ): वह निकाय जिसने गाजा के संबंध में 2024 का आदेश जारी किया।
पद	फ्रांसेस्का अल्बनेज़: स्थिति पर रिपोर्ट करने वाली UN Special Rapporteur।
तथ्य	फिलिस्तीनी अधिकारियों द्वारा अनुमान है कि 8,000 से अधिक लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं।

मेन्स प्रश्न युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और संघर्ष क्षेत्रों में फॉरेंसिक साक्ष्यों के संरक्षण में अंतराष्ट्रीय न्यायिक निकायों और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

Gulf में तनाव के बीच 10 मिलियन भारतीयों की सुरक्षा और एनर्जी सप्लाई पर फोकस

चर्चा में क्यों | गल्फ क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच 10 मिलियन भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के उपायों पर संसद की विदेश मामलों की परामर्श समिति ने चर्चा की।

संस्था	विदेश मामलों के लिए संसद की परामर्शदात्री समिति: भारत की विदेश नीति की देखरेख करने वाली एक संसदीय संस्था।
तथ्य	खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की संख्या: लगभग 10 मिलियन।
तथ्य	प्रमुख खाड़ी भागीदारों पर चर्चा की गई: UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman और Bahrain।

मेन्स प्रश्न क्षेत्रीय भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों की रक्षा करने में भारत की 'लुक वेस्ट' (Look West) नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नागा कम्युनिटी को लौटाए 39 लोगों के अवशेष

चर्चा में क्यों | ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पिट रिवर्स संग्रहालय ने 'फोरम फॉर नागा रिकॉन्सिलिएशन' द्वारा किए गए प्रत्यावर्तन अनुरोध के पश्चात, पूर्वोत्तर भारत के नागा समुदाय को औपनिवेशिक काल के 39 अवशेष वापस करने की घोषणा की है।

संस्था	पिट रिवर्स म्यूजियम: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्थित एक संग्रहालय।
तथ्य	39 अवशेषों को वापसी के लिए अनुमोदित किया गया; एक सेट को बाहर रखा गया।
तथ्य	अवशेषों को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान एकत्र किया गया था।

मेन्स प्रश्न औपनिवेशिक काल के मानव अवशेषों और कलाकृतियों की वापसी की ओर बढ़ते वैश्विक आंदोलन के नैतिक और कानूनी निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

अर्थव्यवस्था

7

FISCAL POLICY, BUDGET & TAXATION (GST)

P

M

8 सितंबर • The Hindu • satyadheesh.in/news/119203

9,222 करोड़ रुपये का फंड नहीं ट्रांसफर हुआ, PAC ने जताई चिंता

चर्चा में क्यों लोक लेखा समिति (PAC) ने CAG की रिपोर्ट संख्या 6, 2026 में रेखांकित किए गए चार निर्दिष्ट आरक्षित कोषों में ₹9,222 करोड़ के सेस और लेवी संग्रह के हस्तांतरण न होने पर चिंता व्यक्त की है।

संस्था | लोक लेखा समिति (PAC): एक संसदीय समिति जो सरकार द्वारा धन के विनियोग और व्यय की जांच करती है।

तथ्य | ₹9,222 करोड़: रिपोर्ट किए गए वे सेस और लेवी संग्रह जिन्हें निर्दिष्ट आरक्षित कोष में स्थानांतरित नहीं किया गया।

मेन्स प्रश्न **सेस और लेवी (Cess and Levy) के संग्रह के प्रबंधन में राजकोषीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।**

CAPITAL MARKETS & SEBI

P

8 सितंबर • Economic Times • satyadheesh.in/news/119136

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 30,000 करोड़ का IPO, हुंडई मोटर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता है

चर्चा में क्यों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) लगभग 30,000 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च कर रहा है, जो संभावित रूप से अब तक की भारत की सबसे बड़ी पेशकश बन सकता है।

तथ्य | NSE IPO का आकार: लगभग Rs 30,000-करोड़।

तथ्य | NSE IPO ऑफर फॉर सेल: 148.9 मिलियन शेयरों तक।

तथ्य | बैंक ऑफ बडौदा का विनिवेश: इसकी हिस्सेदारी का 35%।

संस्था | SEBI: वह नियामक संस्था जिसने NSE IPO के लिए मंजूरी प्रदान की।

तथ्य | Hyundai Motor India IPO का आकार: Rs 27,870-crore (2024)।

मेन्स प्रश्न **भारत के पूंजी बाजारों को गहरा करने में बड़े पैमाने पर होने वाले आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) के महत्व और निवेशकों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में सेबी (SEBI) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।**

MONETARY POLICY, RBI & BANKING

P

8 सितंबर • Economic Times • satyadheesh.in/news/119081

RBI स्वैप फैसिलिटी में भारी उछाल, ICICI बैंक ने सबसे ज़्यादा फंड जुटाए

चर्चा में क्यों RBI की डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा में ₹1,706 बिलियन के प्रवाह का नेतृत्व ICICI Bank ने किया, जिसमें 31 अगस्त तक संचयी प्रवाह \$136.4 बिलियन तक पहुँच गया।

तथ्य | RBI स्वैप सुविधा में \$136.4 बिलियन के संचयी अंतर्वाह (cumulative inflows) में FCNR(B) जमा की हिस्सेदारी 93% रही।

तथ्य | ICICI Bank को डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा में ₹1,706 बिलियन का सर्वाधिक इनफ्लो प्राप्त हुआ।

संस्था | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तरलता प्रबंधन के लिए डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा का प्रबंधन करता है।

मेन्स प्रश्न **भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तरलता प्रबंधन और जमा वित्तपोषण के दबावों को नियंत्रित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्वैप सुविधाओं और FCNR(B) जमाओं के योगदान का विश्लेषण कीजिए।**

इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के डेटा से पता चला है कि साल की पहली छमाही (H1) में ग्लोबल माइन

चर्चा में क्यों इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने वैश्विक खनन उत्पादन में गिरावट की सूचना दी है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय केबल निर्माण कंपनियों में 21,500 करोड़ रुपये की बाजार बिकवाली दर्ज की गई है।

तथ्य	H1 में वैश्विक खनन उत्पादन में 1.1% की गिरावट आई।
संस्था	International Copper Study Group: वैश्विक तांबे के उत्पादन का डेटा प्रदान करने वाली संस्था।
तथ्य	सूचीबद्ध केबल निर्माताओं में ₹21,500 करोड़ की मार्केट सेलऑफ।
पद	Codelco और Freeport-McMoRan Inc.: प्रमुख वैश्विक कॉपर उत्पादक।

मेन्स प्रश्न वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले व्यवधानों का भारत के विनिर्माण क्षेत्र और हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे की ओर संक्रमण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, भारतीय सरकार और LIC से लगभग 53,000 करोड़ रुपये में IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए अग्रणी कंपनी के रूप में उभरी है

चर्चा में क्यों फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, भारतीय सरकार और LIC से लगभग 53,000 करोड़ रुपये में IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए अग्रणी कंपनी के रूप में उभरी है।

तथ्य	Fairfax Financial Holdings का प्रस्ताव मूल्य: Rs 81 प्रति शेयर।
तथ्य	ऑफर के समय IDBI Bank की क्लोजिंग प्राइस: Rs 90.71
तथ्य	60.72% हिस्से का कुल मूल्यांकन: Rs 53,000 करोड़ (\$5.5 billion)।
संस्था	IDBI Bank में हिस्सेदारी की बिक्री: भारत सरकार और Life Insurance Corporation (LIC) द्वारा।
तथ्य	संभावित विलय: अधिग्रहण के पश्चात CSB Bank का IDBI Bank के साथ विलय।

मेन्स प्रश्न भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के भारतीय बैंकिंग परिदृश्य और वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

NSE का IPO लाएगा 30,000 करोड़ रुपये, 18 सितंबर से खुलेगा

चर्चा में क्यों SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO के लिए ड्राफ्ट ऑफर दस्तावेज़ को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से ऑफर फॉर सेल (OFS) के द्वारा लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।

संस्था	SEBI: वह बाजार नियामक जिसने NSE के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी।
तथ्य	NSE IPO: Offer for Sale (OFS) के माध्यम से लगभग Rs 30,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद है।
तथ्य	OFS विवरण: लगभग Rs 1,800 प्रति शेयर की दर पर 14.89 करोड़ तक के इक्विटी शेयर।
तथ्य	सहभागी संस्थाएं: State Bank of India, Bank of Baroda, Stock Holding Corporation, GIC, New India Assurance, National Insurance Company, और United Insurance Company।
तथ्य	लिस्टिंग समयसीमा: IPO 18 सितंबर को खुलेगा और इसका लिस्टिंग 25 सितंबर तक निर्धारित है।

मेन्स प्रश्न भारत में पूंजी बाजार के विकास और राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ में, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश के महत्व पर चर्चा कीजिए।

मिजोरम में वोटर लिस्ट में बदलाव, 6,963 नए वोटर जुड़े

चर्चा में क्यों मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पूर्ण होने की घोषणा की है, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं की संख्या में शुद्ध रूप से 6,963 की वृद्धि हुई है।

तथ्य	विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मिजोरम की कुल मतदाता संख्या 8.35 लाख तक पहुँच गई।
तथ्य	आइजोल जिले में मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या 2.78 लाख दर्ज की गई।
तथ्य	Hnahthial जिले में मतदाताओं की सबसे कम संख्या 15,522 दर्ज की गई।
तथ्य	SIR अभ्यास के परिणामस्वरूप मतदाताओं की संख्या में 6,963 की शुद्ध वृद्धि हुई, जो 0.84% की वृद्धि को दर्शाती है।
पद	गरिमा गुप्ता मिजोरम की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) के रूप में कार्यरत हैं।

मेन्स प्रश्न लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता और हाशिए पर स्थित पहचानों के समावेशी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में समय-समय पर मतदाता सूची के संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1

AI ने सुलझाई 200 साल पुरानी मैथ्स प्रॉब्लम, OpenAI और रिसर्चर्स में विवाद

चर्चा में क्यों OpenAI ने 1,000 से अधिक AI एजेंटों का उपयोग करके 200 वर्ष पुराने नेवियर-स्टोक्स (Navier-Stokes) समीकरण को हल करने की घोषणा की है, जिससे शोधकर्ता ट्रिस्टन बकमैस्टर और लेवेंट अल्पोगे के साथ श्रेय (credit) को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

विज्ञान	Navier-Stokes equation: द्रव गतिकी (fluid dynamics) से संबंधित एक 200 वर्ष पुरानी गणितीय समस्या।
विज्ञान	Clay Millennium Prize: सात गणितीय समस्याओं का एक समूह, जिनके समाधान के लिए \$1 million का पुरस्कार दिया जाता है।
तथ्य	OpenAI ने कुछ ही दिनों के भीतर समाधान पूरा करने के लिए 1,000 से अधिक AI agents का उपयोग किया।

मेन्स प्रश्न जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए जनरेटिव एआई (Generative AI) के उपयोग से उत्पन्न होने वाले नैतिक और बौद्धिक संपदा संबंधी निहितार्थों तथा एआई-आधारित अनुसंधान में श्रेय (credit) के निर्धारण से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

आंतरिक सुरक्षा

1

इमिग्रेशन केस में NIA ने 7 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की

चर्चा में क्यों राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सात व्यक्तियों, जिनमें छह यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक शामिल हैं, के विरुद्ध अपनी पहली आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल किया है।

संस्था	NIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी है।
तथ्य	NIA ने 180 दिनों की जांच अवधि के बाद चार्जशीट दाखिल की।
तथ्य	अभियुक्तों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक यू.एस. नागरिक शामिल हैं।
स्थान	म्यांमार: वह स्थान जहाँ अभियुक्तों ने कथित तौर पर भारत-विरोधी समूहों को प्रशिक्षित किया था।

मेन्स प्रश्न म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में विदेशी नागरिकों और गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) से जुड़े सीमा पार अपराधों की जांच और अभियोजन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ · हर रविवार साप्ताहिक · हिंदी और अंग्रेज़ी · मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh · satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।